Bussiness Standard 12 April 2012

UP MSMEs present road map for overall sectoral development

VIRENDRA SINGH RAWAT
Lucknow, 11 April

Uttar Pradesh's micro, small and medium enterprises (MSMEs) today presented a roadmap for the development of the sector.

In consolidated terms, UP has over 3.1 million MSMEs, including 760,000 and 2.34 million units in the manufacturing and services sector.

The sector provides employment to over five million people in UP with the state accounting for about 12 per cent of the Indian MSME base. It accounts for eight per cent of the state gross domestic product (SGDP) of about ₹6,00,000 crore (current prices).

MSME chamber Indian Industries Association (IIA) today handed over the set of suggestions to state minister for small scale industries (SSI) and export promotion (independent charge) Bhagwat Sharan Gangwar here.

The chamber also held a felicitation function for him. Another similar ceremony was held for Prof Abhishek Mishra, UP protocol minister (attached to chief minister Akhilesh Yadav), later in the evening.

Elaborating thrust points, IIA president Jugal Kishore said implementation of purchase and price preference policy for MSME, which was scrapped by the previous government, was vital for the uplift of the sector.

The chamber suggested that the government organised a large MSME convention in Lucknow every year to be chaired by the state chief minister and presided by the SSI minister. "The manufacturing sector is shrinking fast, which may pose a serious problem for employment generation in the state," Kishore added.

Other key proposals included a separate industrial MSME policy in UP; resolution to the problem of non-availability of land for setting up MSME units; enhancing the effectiveness of Udyog Bandhu' separate house tax rates for industrial properties; 24 hrs availability of electricity to industry; proper implementation of single table system; implementation of effective rehabilitation policy for sick MSMEs and formation of rehabilitation board; simplification of labour law procedures; simplified and uniform VAT; assistance for enhancement of technology and incentives for setting up MSMEs in backward areas.

jk’Vh; lgkjk 12 vizy 2012

लघु उद्योगों के लिए अलग नीति बने : आईआईए

लखनऊ (एसएनबी)। लघु उद्योगों के संगठन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने लघु उद्योगों के उत्थान और विकास के लिए एक प्रस्ताव प्रदेश के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भगवत शरण गंगवार को आज यहां गोमती नगर स्थित आईआईए भवन में आयोजित सम्मान समारोह में सौंपा। आईआईए के केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों, मण्डलीय अध्यक्षों एवं चैप्टर अध्यक्षों ने लघु उद्योग मंत्री को सम्मानित किया। प्रस्ताव में आईआईए के अध्यक्ष जुगल किशोर ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए क्रय एवं मूल्य वरीयता नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है। और उद्योग निदेशालय की दर संविदा प्रक्रिया (रेट कान्ट्रेक्ट सिस्टम) को पूर्ववत् अतिशीघ्र बहाल करने के आग्रह किया है।

उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने के साथ-साथ लघु उद्योगों के लिए अलग से उद्योग नीति बनाने की मांग की है तथा श्रम कानूनों को भी सरल बनाने का आग्रह किया है। जुगल किशोर ने कहा कि प्रदेश के लघु उद्यमियों के लिए वर्ष में एक बार लघु उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्यमंत्री द्वारा की जाए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हों।

ik;fuj 13 vizy 2012

प्रदेश की एमएसएमई समस्याओं का जल्द होगा निवारण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आईआईए ने अभिषेक मिश्रा व गंगवार को किया सम्मानित

रखीं सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की समस्याएं, मिला निराकरण का आश्वासन

इंडियन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन (आईआईए) ने बुधवार को अलग-अलग सम्मान समारोहों में राज्य मंत्री प्रोटोकॉल अभिषेक मिश्रा एवं लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भगवत शरण गंगवार को सम्मानित किया। दोनों ही मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्योगों(एमएसएमई) की समस्त समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया और कहा कि वे यथाशीघ्र एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की बैठक मुख्य मंत्री से करवायेंगे।

राज्य मंत्री प्रोटोकाल अभिषेक मिश्रा ने कहा कि सरकारी नौकरी से राज्य की बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिए शहर, कस्बों एवं गांव-गांव में सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्यमों की अपरिहार्यता है तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। इसके लिए एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा और सरकार आपके साथ है। हम आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए जल्द ही आपके प्रतिनिधि मंडल की बैठक मुख्य मंत्री के साथ करायेंगे। वहीं दूसरी ओर लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भगवत शरण गंगवार ने कहा कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग की वकालत करने वाली आपकी संस्था की राय से सरकार काम करेगी। सरकार की प्राथमिकता उद्योगों को बढ़ावा देने की है इसलिए हम प्रदेश के लघु उद्योगों की समस्त समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं और इसके लिए मुख्य मंत्री भी आपके साथ हैं।

आईआईए के अध्यक्ष जुगुल किशोर ने दोनों मंत्रियों के समक्ष प्रदेश के एमएसएमई की समस्याओं के प्रमुख पहलुओं को रखा जिनमें उद्योग बंधु को पुनर्जीवित कर सशक्त बनाना, क्रय व मूल्य वरीयता, डीआई रेट कांट्रेक्ट सिस्टम, उद्योगों पर गृह कर की नयी व्यवस्था, बिजली की अनुपलब्धता, लघु उद्योग के लिए अलग औद्योगिक नीति, रुग्ण इकाईयों की पुनर्वासन नीति एवं वैट व प्रवेश कर का सरलीकरण आदि रहीं।

nfud tkxj.k 12 vizy 2012

अभिनंदन

आइआइए ने बुधवार को यहां लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री भगवत शरण गंगवार को सम्मानित किया। इस मौके पर आइआइए की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगो के उत्थान के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। आइआइए के अध्यक्ष जुगल किशोर ने प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य वरीयता नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह भी कहा कि उद्योग निदेशालय की दर संविदा प्रक्रिया को अतिशीघ्र बहाल किया जाना जरूरी है। उन्होंने लघु उद्योगो के लिए अलग से नीति बनाये जाने की भी वकालत की। समारोह में आइआइए की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तथा मंडल व चैप्टर अध्यक्ष शामिल थे।

The Times of India 12 April

IIA HONOURS BHAGWAT SARAN GANGWAR

IIA felicitated state minister for small-scale indrustry (SSI) and export promotion Bhagwat Saran Gangwar and proposed action for Medium Small Micro Enterprise (MSME) development at a felicitation ceremony on Wednesday.

Elaborating on the key points of proposal, IIA president Jugal Kishore said: "Implementation of purchase and price preference policy for MSMEs and restoration of Directorate Industry rates, and contract system, which was scrapped by the previous government, is necessary for the sector's uplift."

He said Mulayam Singh Yadav during his chief ministership gave orders to abolish 'Inspector Raj' but it was not being complied with, therefore, IIA proposed to revive these orders.

Function: Indian Industries Association (IIA), the apex body of micro, small and medium enterprises organised a function here on Wednesday to honour minister of state for SSI and export promotion (independent charge) Bhagwat Sharan Gangwar.

The Times of India 11 April

Felicitation: Indian Industries Association (IIA) is organising two felicitation functions at IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomtinagar on Wednesday. The first function is being held at 4 pm to honour minister of state for small scale industries and export promotion (independent charge) Bhagwat Sharan Gangwar, while the second function will be held at 7.30 pm in honour of minister of state for protocol (attached to the CM) Abhishek Mishra. During the functions, IIA will submit proposals to both the dignitaries for the development of micro, small and medium enterprises in UP.

tuln"k VkbEl 12 vizy 2012

आईआईए मंत्री से मिला

लखनऊ। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) की प्रदेश इकाई ने बुधवार को राज्य के लघु उद्योग मंत्री भगवत शरण गंगवार से मिलकर उन्हें उद्यमियों की परेशानियों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने लघुउद्योग मंत्री से समस्याओं को दूर करने के सुझाव दिये। उद्यमियों ने बड़ी, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयोंको बढ़ाने के लिए कई आवश्यक सुझाव दिये और दावा किया कि यदि सरकार इन पर सकारात्मक रुख अपनाती है ,तो राज्य में पूंजी निवेश तो बढ़ेगा ही, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ब्यूरो

bfUd ykch utj 13 viz 2012

उद्यमियों ने सरकार को दिये सुझाव

लखनऊ, 11 अप्रैल। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन की प्रदेश इकाई ने आज राज्य के लघु उद्योग मंत्री भगवत शरण गंगवार से मिलकर उन्हें उद्यमियों की परेशानियों से अवगत कराया और उसे दूर करने के सुझाव दिये। उद्यमियों ने बडी, लघु और मध्यम उद्योग इकाईयों को बढ़ाने के लिए कई आवश्यक सुझाव दिये और दावा किया कि यदि सरकार इन पर सकारात्मक रुख अपनाती है तो राज्य में पूंजी निवेश तो बढ़ेगा ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। आईआईए के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि पर्चेज ऐण्ड परफारमेंन्स पालसी को दुरुस्त किया जाना चाहिए।

इससे राज्य में उद्योग का माहौल तैयार होगा। बिस्कुट बनाने की बडे पैमाने पर मशीन बनाकर देश के साथ ही विदेशों में भेजने वाले एखलाक अहमद खां ने कहा कि ८० के दशक में उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनने के बाद राज्य सरकार ने उद्यमियों को १५ से २५ प्रतिशत कैप्टल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पांच से छह वर्षों के लिए बिक्रीकर में छूट, यूपीएसआईडीसी की लैण्ड पर सब्सिडी और डीजी सेट के केबीए पर भी छूट की व्यवस्था थी। श्री अहमद ने कहा कि पिछले करीब दस वर्षों से यह सारी सुविधा समाप्त हो गयी है जिसके कारण नये उद्योग लगाने के लिए लोग दूसरे प्रदेशों में भाग रहे हैं। राज्य के संवेदनशील जिलों में शुमार फैजाबाद में अपना उद्योग चला रहे श्री खां ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में निर्मित प्लाण्ट एवं मशीनरी पर लगभग १२ प्रतिशत वैट लगाने से प्रदेश का व्यापारी अपने राज्य से उन प्लाण्ट एवं मशीनरियों को नहीं खरीदता है क्योंकि उसे वही प्लाण्ट एवं मशीनरी प्रदेश के बाहर से लाने पर केवल दो से चार प्रतिशत कर देना पड़ता है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के व्यापार और उद्योग पर पड़ रहा है। लघु उद्योगों में प्रथम पुरस्कार पाकर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से सम्मानित हो चुके श्री खां ने कहा कि जिला उद्योग केन्द्रों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि सरकार की योजनाओं का सही समय पर पता चल सके। उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव सरकार के कार्यकाल में इन्सपेक्टर राज खत्म करने का वायदा किया गया था।

उस वायदे को पूरा करने का सही समय अब आया है क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उद्यमियों की प्रतिवर्ष बैठक या सम्मेलन कराने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि उद्योग जगत में निर्माण इकाइयों का धीरे-धीरे समापन हो रहा है। यह काफी दुखद है और इससे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने अलग से उद्योग नीति बनाने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि उद्योगबंधु उद्यमियों की समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं करवा पा रहा है।

fgUnLrku 12 viz 2012

आईआईए ने लघु उद्योगों के तरक्की के उपाय सुझाए

लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने बुधवार को प्रदेश के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री भगवत शरण गंगवार को सम्मानित किया। इस मौके पर आईआईए द्वारा सूक्ष्म एवं मध्यम एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) के विकास के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव सौंपते हुए आईआईए के अध्यक्ष जुगल किशोर ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई की तरक्की के लिए क्रय एवं मूल्य वरीयता नीति का कड़ाई से पालन होना चाहिए। साथ ही उद्योग निदेशालय की दर संविदा प्रक्रिया (रेट कांट्रेक्ट सिस्टम) को बहाल करना जरूरी है। उन्होंने अलग उद्योग नीति, औद्योगिक भूमि के लिए संपत्ति कर का अलग वर्गीकरण, श्रम कानूनों में सुधार और सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा तत्परता से लागू कराने का प्रस्ताव सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्यमियों के लिए साल में एक बार मुख्यमंत्री और लघु उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में लघु उद्यमी महासम्मेलन आयोजितकिया जाना चाहिए। इस मौके पर आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद मिगलानी, संजय कौल, जीसी चतुर्वेदी मौजूद रहे।

राज्य मंत्री अभिषेक मिश्र सम्मानित

लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से विभूतिखण्ड स्थित आई आईए भवन में आयोजित समारोह में राज्यमंत्री, प्रोटोकॉल प्रो. अभिषेक मिश्र को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन अध्यक्ष ने लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु प्रस्ताव पेश किया। जिसमें उद्योग बंधु को पुनर्जीवित करने, लघु उद्योगों के लिए अलग औद्योगिक नीति बनाने व वैट व प्रदेश कर के सरलीकरण करने की मांग की।

vkt 12 viz 2012

लघु उद्यमियों ने सरकार को उद्योग बढ़ाने के दिये सुझाव

□आज वित्त समाचार सेवा

लखनऊ 11 अप्रैल। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) की उत्तर प्रदेश इकाई ने आज राज्य के लघु उद्योग मंत्री भगवत शरण गंगवार से मिलकर उन्हें उद्यमियों की परेशानियों से अवगत कराया और उसे दूर करने के सुझाव दिये। उद्यमियों ने बड़ी, लघु और मध्यम उद्योग इकाईयों को बढ़ाने के लिए कअी आवश्यक सुझाव दिये और दावा किया कि यदि सरकार इन पर सकारात्मक रुख अपनाती है तो राज्य में पूंजी निवेश तो बढेगा ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। आईआईए के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर ने अपनी मांगों काएक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि पर्चेज ऐण्ड परफारमेंन्स पालसी को दुरुस्त किया जाना चाहिए। इससे राज्य में उद्योग का माहौल तैयार होगा।

सरकार का सकारात्मक रूख हुआ तो राज्य में बढ़ेगा पूंजी निवेश-आईआईए

बिस्कुट बनाने की बडे पैमाने पर मशीन बनाकर देश के साथ ही विदेशों में भेजने वाले एखलाक अहमद खां ने कहा कि 80 के दशक में उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनने के बाद सरकार ने उद्यमियों को 15 से 25 प्रतिशत कैप्टल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पांच से छह वर्षों के लिए बिक्रीकर में छूट, यूपीएसआओीडीसी की लैण्ड पर सब्सिडी और डीजी सेट के केबीए पर भी छूट की व्यवस्था थी। श्री अहमद ने कहा कि पिछले करीब दस वर्षों से ये सारी सुविधाए समाप्त हो गयी है जिसके कारण नये उद्योग लगाने के लिए लोग दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं। राज्य के संवेदनशील जिलों में शुमार फैजाबाद में अपना उद्योग चला रहे श्री खां ने कहा कि इसके अलावा राज्य में निर्मित प्लाण्ट एवं मशीनरी पर लगभग 12 प्रतिशत वैट लगाने से व्यापारी अपने राज्य से उन प्लाण्ट एवं मशीनरियों को नहीं खरीदता है क्योंकि उसे वही प्लांट एवं मशीनरी राज्य के बाहर से लाने पर केवल दो से चार प्रतिशत कर देना पडता है। इसका सीधा असर राज्य देश के व्यापार और उद्योग पर पड रहा है। लघु उद्योगों में प्रथम पुरस्कार पाकर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से सम्मानित हो चुके श्री खां ने कहा कि जिला उद्योग केन्द्रों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि सरकार की योजनाओं का सही समय पर पता चल सके। उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव सरकार के कार्यकाल में इन्सपेक्टर राज खत्म करने का वायदा किया गया था। उस वायदे को पूरा करने का सही समय अब आया है क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उद्यमियों की प्रतिवर्ष बैठक यासम्मेलन कराने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि उद्योग जगत में निर्माण इकाइयों का धीरे.धीरे समापन हो रहा है। यह काफी दुखद है और इससे बेरोजगारी लगातार बढती जा रही है। उन्होंने अलग से उद्योग नीति बनाने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि उद्योगबंधु उद्यमियों की समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं करवा पा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीयन कराने कीभीड से ही स्पष्ट है कि राज्य में कितनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कल-कारखानों का लगना बहुत जरुरी है और इसके लिए इन्सपेक्टरराज और भ्रष्टाचार की समाप्ति अत्यन्त जरुरी है।